

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 27, मंगलवार, शाके 1945-जुलाई 18, 2023 Asadha 27, Tuesday, Saka 1945- July 18, 2023	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 18, 2023

संख्या एफ. 13(20)विशा/विस/2023/ :-राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन)
विधेयक, 2023 जैसा कि दिनांक 18 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधान सभा में
पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,

प्रमुख सचिव ।

Bill No.20 of 2023

THE RAJASTHAN CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2023

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 8, Rajasthan Act No. XXX of 1952.- For the existing section 8 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Act No. XXX of 1952), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Penalties for contravention of Act and Rules thereunder.-If the owner or person incharge of a cinematograph uses the same or allows it to be used or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Act or of the rules made thereunder or of the terms, conditions and restrictions upon or

subject to which any licence under this Act has been, or is deemed to have been granted he shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to five thousand rupees for each day during which the offence continues.”.

3. Deletion of section 8-A, Rajasthan Act No. XXX of 1952.-The existing section 8-A of the principal Act shall be deleted.

4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. XXX of 1952.- For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“9. Power to revoke licence.- Where the holder of a licence has been convicted of an offence under section 7 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act No. 37 of 1952) or under section 8 of this Act or for the commission of any offence under the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the licence may be revoked by the licensing authority.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 was enacted to make provisions for regulating exhibitions by means of cinematographs. The existing section 8 of the Act provides for penalties for contravention of the Act and rules made thereunder. In present context, the penalties are very meager under this Act. The State Government has felt the necessity to revise the rate of penalties. Accordingly, section 8 is proposed to be amended suitably.

It is also found appropriate to decriminalise the offences under this Act. Therefore, the existing section 8-A, which provides for power to arrest without warrant, has now become redundant. Therefore, section 8-A is proposed to be deleted. Thus, consequential amendment is also being proposed in section 9 of the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

2023 का विधेयक सं.20

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं. 30), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियां.- यदि, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बन्धनों, जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है या प्रदान की गयी समझी गयी है, का उल्लंघन करते हुए, यदि सिनेमा यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उस सिनेमा यंत्र का उपयोग करता है या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का उपयोग करने देता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

3. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-क हटायी जायेगी।

4. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने की शक्ति.- जहां किसी अनुज्ञप्ति धारक को चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 7 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी अपराध का या राजस्थान मनोरंजन और

विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) के अधीन कोई अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत की जा सकेगी।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 सिनेमा यंत्रों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों को विनियमित करने के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की विद्यमान धारा 8, अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियों का उपबन्ध करती है। वर्तमान संदर्भ में, इस अधिनियम के अधीन शास्तियां बहुत कम हैं। राज्य सरकार ने शास्तियों की दर को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की है। तदनुसार धारा 8 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का गैर-अपराधीकरण किया जाना भी समुचित पाया गया है। इसलिए विद्यमान धारा 8-क, जो बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति का उपबंध करती है, अब अनावश्यक हो गयी है। अतः धारा 8-क हटायी जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार से अधिनियम की धारा 9 में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Government Central Press, Jaipur.